Special Purposes Vehicle (SPV) formulated for Smart City initiatives

New Delhi – April 26, 2016

The major projects related to public services, social infrastructure, better regulation and creation of a Special Purpose Vehicle (SPV) under Smart City initiatives has been approved by the Council of NDMC in a meeting held today, presided by Hon'ble Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal. The SPV will be a Public Limited Company, wholly owned by NDMC, incorporated underCompanies Act, 2013 at the city level.

The Council has approved the proposal for formation of Special Purpose Vehicle under Smart Cities Mission of the Ministry of Urban Development, Government of India on behalf of NDMC, as required to implement the Smart City initiatives within the NDMC area.

In order to facilitate the residents of New Delhi area, the Council decided that birth and death certificate may be available through digital platform, free of cost. Henceforth residents need not physically access NDMC offices and can get the same downloaded from NDMC's website while sitting at home. This initiative is intended to make civic services hassle free through ICT intervention and provide a fillip towards digital India.

To provide better social infrastructure in its jurisdictional area, the Council has approved the establishment of 118 Water ATMs to provide affordable and quality drinking water which shall meet BIS 14543 standards i.e. equivalent to packaged drinking water. Additionally, the Council approved to award the work of construction of 70 Smart Public Toilets Units in NDMC area in consonance with Swachh Bharat Mission of Government of India.

With a view to provide quality education, the Council approved to set up Smart Class Rooms in 444 classrooms of 30 schools out of 51 schools from class VI to XII under the NDMC in first phase, having features such as CCTV cameras and Short-Throw Projectors in each smart classroom. The smart education initiatives aimed at introducing e-Learning solution in all NDMC

schools so as to transform traditional classrooms enable smart learning classrooms by introduction of state-of- art technology, infrastructure and professionally developed learning content.

NDMC has adopted the Solid Waste Management Rules, 2016 notified by the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change on 8th April, 2016. This will enable NDMC to introduce user charges for its door-to-door solid waste collection facility.

The Council has approved the proposal under Public Private Partnership (PPP) mode for providing free WiFi service upto 1 GB data per month (atleast 50 MB data per day) at selected hot-spots in NDMC area, to install 2261 CCTV cameras for increased safety and security of citizens, especially women, children and elderly, which will be connected to a Central Command and Control Centre through an optical fibre. This project includes replacement of all street lights with energy efficient LED lights having smart features. This project will be implemented through selection of a Concessionaire on PPP mode in lieu of use of Street Light Pole for hosting telecom services and use of Right of Way for laying optical fiber. This will enable NDMC to provide state-of-the-art services to the citizen in an inclusive manner.

Presently, the responsibility of maintaining water pipe-line from ferrule point to the consumer water meter is of the consumer. The Council observed that house service connection pipelines are many times found damaged or corroded resulting in wastage of water and also complaints of contamination resulting in health hazards. As a result, the Council has decided to take over the responsibility to develop and maintain water supply infrastructure upto water meter to arrest leakages and prevent contamination of water.

A proposal for providing parking guidance and management solution for on-street, off-street and indoor parking spaces in NDMC area on PPP mode has also approved. These parking lots are of 3 categories i.e. street parking lots, surface parking lots and covered parking lots. The project intends to identify

availability of parking slots through sensors on real time basis, thereby enabling drivers to identify parking slots through a mobile app.

The Council also approved a project for installation of interactive digital information panel at various places in NDMC area so that the users can connect to the online digital world through these interactive panels, in lieu of advertisement rights on these panels under PPP mode.

The Unified Building Bye Laws for Delhi 2016 notified on 22nd march, 2016 has been adopted by the Council to provide online single window clearances for building plan approvals. This will enable time-bound hassle free disposal thereby enhancing the ease of doing business in the NDMC area.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए स्पेशल प्रपस व्हीकल कम्पनी का गठन

नई दिल्ली – 26 अप्रैल, 2016

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की बैठक में आज जन सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं और बेहतर नियमों के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए स्पेशल प्रपस व्हीकल (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दे दी गई । इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने की । एसपीवी एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होगी जो पूर्णत: पालिका परिषद् के स्वामीत्व में रहेगी इसको कम्पनी एक्ट 2013 के तहत सिटी लेवल पर बनाया गया है ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने एसपीवी के गठन के प्रस्ताव को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं को नई दिल्ली में पूरा करने के लिए मंजूरी दी है । एसपीवी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने, उसके अनुमोदन, धन आबंटीत करने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्याकंन करेगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के निवासियों को नि:शुल्क जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है । अब पालिका परिषद् क्षेत्र के निवासियों को इन प्रमाण–पत्रों के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नही होगी, वे घर बैठे नदिनप वेबसाइट से इन्हें डाउलोड कर सकेगें । यह प्रयास जनता को बिना किसी दुविधा के सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐसा कदम है जो डिजीटल इंडिया की ओर अग्रसर करता है ।

पालिका परिषद् अपने क्षेत्र में सामाजिक आधारभूत सरंचनाओं को उन्नत करने के लिए 118 वाटर एटीएम के माध्यम से उत्तम गुणवता वाले पेयजल को उपलब्ध कराएगी । इसके साथ ही 70 स्थानों पर स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम होगा ।

पालिका परिषद् क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को और उन्नत करने की दिशा में पालिका परिषद् ने आज निर्णय किया है कि प्रथम चरण में 51 में से 30 नगर

पालिका विद्यालयों की कक्षा छह से कक्षा बारहवीं की 444 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रूम में बदला जाएगा । इन कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरें, शॉट-थ्रो प्रोजेक्टर, ई-लर्निंगं समाधान जैसी सुविधाए पढाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 को आज पालिका परिषद् क्षेत्र में लागू करने के लिए अनुमोदन कर दिया है जिसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया था । इसके अन्तर्गत पालिका परिषद् अब घर-घर से ठोस कूड़ा इकट्ठा करने की सुविधा के लिए शुल्क प्रभार भी लगाएगी ।

पालिका परिषद् अपने क्षेत्र में निजी जन भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के आधार पर बिजली के खम्बों पर वाई-फाई एनटीना, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लाइट जैसे सुविधाए उपलब्ध कराएगी । इससे लोगो को फ्री वाई-फाई और सुरक्षा उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही उर्जा की बचत होगी।

पालिका परिषद् क्षेत्र में अबतक पानी की पाइप लाइन की पानी के मीटर तक की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती थी लेकिन देखा यह गया था की यह पाइप लाइन टूटने फूटने से पानी का बहाव होता था, जो की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता था । अब पालिका परिषद् ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की जिम्मेदारी वह खुद वहन करेगी और इसके विकास और रखरखाव तथा पानी के ऐसे बहाव को रोकने और दूषित होने को भी रोकेगी ।

पालिका परिषद् ने पीपीपी मॉडल के आधार पर सड़क पर और सड़क से बाहर तथा परिसरों के अन्दर पार्किंग क्षेत्र के मार्ग दर्शन और प्रबंधन के लिए एक परियोजना का मंजूरी दी है । इसके अन्तर्गत पार्किंग की उपलब्धता उन्नत तकनीक पर आधारित सेंसर द्वारा बताई जा सकेगी तथा कोई भी वाहन चालक मोबाइल ऐप्प से भी पार्किंग की उपलब्धता जान सकेगा ।

पालिका परिषद् ने आज पीपीपी मॉडल आधार पर नई दिल्ली क्षेत्र में ऐसे डीजीटल सूचना पैनल लगाने का अनुमोदन किया है जिससे प्रयोगकर्ता को किसी भी जानकारी के लिए इनका उपयोग डिजीटल माध्यम के रूप में कर सकेगें ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने आज 22 मार्च 2016 को अधिसूचित किए गए दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम - 2016 को भी पालिका परिषद् में लागू करने को मंजूरी दे दी है । इसके तहत अब पालिका परिषद् क्षेत्र में भवनों के नक्शों का अनुमोदन एकल खिड़की के माध्यम से ऑनलाइन हो सकेगा ।